



पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)



केन्द्रीय कार्यालय: "सौदामिनी" प्लॉट सं. 2, सैक्टर-29, गुडगाँव-122 001, (हरियाणा) दूरभाष: 0124-2571700-719, फ़ैक्स : 0124-2571762,
"Saudamini" Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon-122 001, (Haryana) Tel. : 0124-2571700-719, Fax : 0124-2571762, Web.: www.powergridindia.com

के.आ./के.आ./सू.अ/2014/95

दिनांक : 13th October 2014

श्री जे पी मिश्रा
केअर आफ एल पी मिश्रा
ब्रम्ह कुमारी आश्रम के पास नारायण नगर
आई टी आई रोड होशंगाबाद (.प्र.म)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 12.8.2014 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा आपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी मांगी है।

उत्तर 1 : पावरग्रिड का गठन 23 अक्टूबर, को 1989 राष्ट्रीय पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में किया गया था। इसके बाद संपत्तियों का हस्तांतरण केन्द्रों और राज्यों की विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न चरणों में किया गया है।

उत्तर 2 : पावरग्रिड ट्रांसमिशन उपकेंद्र लाइनों का निर्माण विद्युत अधिनियम के 2003 अधीन करता। उपरोक्त अधिनियमों एवम भारत के राजपत्र की फोटोकॉपी संलग्न है।

उत्तर 3 : पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के उपकेंद्र के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 / एवं से 2014 जनवरी 1 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अधिग्रहित करके उपलब्ध करायी जाती है। मुआवजे की राशि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे को पावरग्रिड सम्बंधित जिले के राजस्व विभाग में जमा करती है, जिसका वितरण सम्बंधित जिले के राजस्व विभाग द्वारा भूमि मालिकों को किया जाता है। मुआवजा राशि के संबंध में सूचना राज्य के राजस्व अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। पावरग्रिड द्वारा कुछ उपकेंद्रों के निर्माण के लिए हाल ही में भूमि की खरीद भूमि मालिक की सहमति से किया जा रहा है।

भारतीय तार अधिनियम,के भाग ॥ 1885 , संभाग 10(बके अनुसार (पावरग्रिड बिजली संचार के तार खिंचने के प्रयोजन से खंबों के लिये भूमि का प्रयोग करती है । खंबों तथा तारों के नीचे स्थित भूमि के अधिग्रहण का कोई प्रावधान नहीं है तथा कार्य के पश्चात भूमि पर खेतीबाड़ी से संबंधित गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं । इसी अधिनियम के भाग ॥1, संभाग 10(द) अनुसार उपयोगकर्ता संस्थान के द्वारा सभी प्रभावित व्यक्तियों को उक्त कार्य के दौरान हुए नुकसान के लिये मुआवजा दिया जाता है । पारेषण लाइन के निर्माण तथा उनके रख रखाव करने के दौरान होने वाली क्षति का जिला राजस्व कार्यालय द्वारा निर्धारित किये गये दर से मुआवजे का भुगतान पावरग्रिड द्वारा किया जाता है। अधिनियम की फोटोकापी संलग्न है।

भारत सरकार के उद्यम, पावरग्रिड कारपोरेशन औफ इंडिया को दिनांक दिसंबर 24 के द्वारा विद्युत अधिनियम (असाधारण) के भारत के राजपत्र 2003, के संभाग 2003 तथा भारतीय तार अधिनियम 164,1885 के भाग ॥1, संभाग के अंतर्गत 19 से 10 पावरग्रिड को, किसी भी अचल सम्पत्ति में या पोस्ट के नीचे, ऊपर, पास में या इसके पार बिजली के संचार हेतु पारेषण लाइन या विद्युत संयंत्र का निर्माण करने तथा उनके रख रखाव करने का-अधिकार प्रदान किया गया है । उपरोक्त दोनों अधिनियमों एवम भारत के राजपत्र की फोटोकापी संलग्न है।

उत्तर 4: उपकेंद्र के निर्माण हेतु, भूमि का अधिग्रहण)राज्य सरकार द्वारा (भूमि अधिग्रहण अधिनियम से 2014 जनवरी 1 एवं 1894 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना जारी की जाती है तथा इसको स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। उपकेंद्र से सम्बंधित अधिसूचना सम्बंधित जिले के राजस्व अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

उत्तर 5 : पावरग्रिड द्वारा अनेक उपकेंद्रों का निर्माण किया गया है जो पूरे देश के विभिन्न राज्यों के अलग अलग जिलों में स्थित हैं। जिनके लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई है। जिनका मुआवजा पावरग्रिड द्वारा सम्बंधित राजस्व विभाग में जमा किया जाता है तथा जिसका वितरण सम्बंधित जिले के राजस्व विभाग द्वारा सम्बंधित जमीन के मालिक को दिया जाता है। इस संदर्भ में सूचना सम्बंधित उपकेंद्र जिस जिले में स्थित है उस जिले के राजस्व विभाग द्वारा प्राप्त की जा सकती है। पारेषण लाइन के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है। पावरग्रिड ने एक लाख से अधिक सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन का निर्माण किया है। पारेषण लाइन के निर्माण के दौरान होने वाली क्षति का जिला राजस्व कार्यालय /

जिला बागवानी (उद्यान) कार्यालय द्वारा निर्धारित दर पर (मुआवाजे का भुगतान लोगो को दिया गया है। पावरग्रिड द्वारा चेक की फोटोकॉपी रखी नहीं जाती है अतः उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है। अगर आप किसी विशेष लाइन की जानकारी चाहते , तो उस लाइन का नाम एवं जगह के बारे में सूचित करें।

उत्तर 6: इस संबंध में क्षेत्रीय मुख्यालय, सबस्टेशन एवं संचरण पथ कार्यालयों के - अनुमोदित मैनुअल नार्म्स की प्रति प्रमाण के रूप में संलग्न है।

उत्तर 7 : आपको अवगत कराना है कि पावरग्रिड में स्थानांतरण निगम की आवश्यकता, हित और जाब रोटेशन को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं । नई परियोजनाओं के लिए कर्मचारियों की तैनाती निगम के कर्मचारियों में से प्रवीणता (स्किल) की उपलब्धता और आवश्यकता के अनुसार की जाती है एवं स्थानांतरित कर्मचारी के स्थान पर आवश्यकतानुसार एवजी की तैनाती की जाती है ।

उत्तर 8: इस संबंध में पावरग्रिड में कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति संलग्न है । आपके द्वारा मांगी गई जानकारी बहुत अधिक मात्रा में है और इसे एकत्रित करने में लोक प्राधिकरण के संसाधनों का विषमतापूर्वक आबंटन होगा । अतः यदि आपको कोई विशिष्ट जानकारी चाहिए तो उपलब्ध कराई जा सकती है ।

इसके अलावा, आप किसी भी कार्य दिवस पर, पूर्व सूचना के साथ, हमारी कंपनी के कार्यालय का दौरा करके किसी विशिष्ट दस्तावेज़/अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट दस्तावेज़/अभिलेखों का निरीक्षण करना चाहते हैं तो आप से अनुरोध है कि अपने प्रस्तावित आगमन की तिथि एवं समय की जानकारी हमें कम से कम दो सप्ताह पहले दें ताकि दस्तावेज़ तैयार रखे जा सकें । कृपया ध्यान रहे कि किसी भी संबंधित दस्तावेज़ की फोटोकॉपी लागू शुल्कों के भुगतान पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।

उत्तर 9: पावरग्रिड केंद्रीय कार्यालय में कर्मचारियों एवं उनके बच्चों के लिए कोई वाहन नहीं लगे हुये है ।

उत्तर 10 : जैसा उत्तर-6 में दिया हुआ है । कर्मचारियों को कार्य की आवश्यकतानुसार दूसरे विभागों में भी नियुक्त किया जाता है जो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात होता है । वर्तमान में कुल 33 (तीस) प्रबन्धक पदनाम के कार्यपालक पावरग्रिड के मानव संसाधन विभाग में कार्यरत हैं ।

उत्तर 11 : इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत परिपत्र की प्रति संलग्न है ।


आर.टी.आई .अधिनियम 2005 के प्रावाधान के अनुसार अपीलीय अधिकारी का विवरण निम्नानुसार:

श्री बी. मिश्रा

कार्यपालक निदेशक (के.आ. एवं आईटी) एवं अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय कार्यालय
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
"सौदामिनी", प्लॉट नं. 2, सैक्ट, 29-
गुड़गांव, 122001-हरियाणा

धन्यवाद ।

भवदीय,



(सुधीर मित्तल)

13.10.14

महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1148]
No. 1148]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2003/पौष 3, 1925
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2003/PAUSA 3, 1925

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2003

का.आ. 1463(अ).—जहाँ पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिनका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली (अब से "पावरग्रिड" नाम से संदर्भित) है, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक सरकारी कंपनी है और विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अंतरराज्यीय पारेषण कार्य के लिए लाइसेंसि है।

और, जहाँ पावरग्रिड द्वारा अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली के जरिए पारेषण प्रणाली स्थापित करना तथा विद्युत पारेषण का कार्य करना अपेक्षित है।

और, जहाँ विद्युत पारेषण या कार्यों के समुचित समन्वयन के लिए आवश्यक दूरभाषीय या तार संबंधी सम्प्रेषण के उद्देश्य से किसी अचल संपत्ति में या पर पोस्ट के नीचे, ऊपर, पास में या इसके पार विद्युत तार या विद्युत संयंत्र स्थापित करने और इनका अनुरक्षण करने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 8) के भाग-3 के अंतर्गत तार लाइनों को विछाने या स्थापित अथवा अनुरक्षित पोस्ट या इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित तार लाइनों एवं पोस्टों के संबंध में पावरग्रिड को शक्तियाँ प्रदान करने एवं पावरग्रिड द्वारा इनका प्रयोग किया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पावरग्रिड को एतद्वारा विद्युत पारेषण के लिए तथा कार्यों के समुचित समन्वयन के लिए आवश्यक दूरभाषीय या तार संबंधी सम्प्रेषण के उद्देश्य से विछाई गयी या अनुरक्षित अथवा विछाई जाने या अनुरक्षित की जाने वाली विद्युत लाइनों एवं विद्युत संयंत्र के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग-3 के अंतर्गत तार प्राधिकरण को प्रदत्त एवं इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

पावरग्रिड को उपर्युक्त शक्ति का प्रत्यायोजन इसके द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन करने की शर्त पर दिया गया है।

[सं. 23/73/2003-आर एंड आर]

अजय शंकर, संयुक्त सचिव

Anders file

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 24th December, 2003

S.O. 1463(E).—Whereas Power Grid Corporation of India Limited, having its registered office at B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi (hereinafter referred to as 'the POWERGRID') is a Government Company registered under the Companies Act, 1956 and a licensee engaged in the business of inter-State transmission of electricity, under the Electricity Act, 2003;

And, whereas Powergrid is required to establish transmission system and to undertake transmission of electricity through inter-State transmission system;

And, whereas for placing and maintaining of electric lines or electrical plant under, over, along or across, posts in or upon any immovable property for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communications necessary for proper coordination of works, the vesting and exercise of the powers of the Telegraph Authority under Part-III of the Indian Telegraph Act, 1885 (8 of 1885) with respect to the placing of the telegraph lines and posts established or maintained or to be so established or maintained are required to be conferred on the Powergrid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 164 of the Electricity Act, 2003 the Powergrid is hereby authorized to exercise all the powers vested in the Telegraph Authority under Part III of the Indian Telegraph Act, 1885, in respect of the electrical lines and electrical plant established or maintained, or to be so established or maintained for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communication necessary for the proper coordination of the works.

The above authorization is subject to compliance by the Powergrid to the requirements of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made thereunder.

[No. 23/73/2003-R&R]

AJAY SHANKAR, Jt. Secy.

UNIVERSAL'S
NEW DELHI - INDIA

The Electricity Act, 2003

(36 of 2003)

with

- The Electricity Rules, 2005
 - The Fees for Making Application for Grant of Licence Rules, 2004
 - The National Electricity Plan Notification Rules, 2004
 - The Appellate Tribunal for Electricity (Salaries, Allowances and Other Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2004
 - The Appellate Tribunal for Electricity (Form, Verification and the Fee for Filing an Appeal) Rules, 2004
 - The Appeal to the Appellate Authority Rules, 2004
 - The Means of Delivery of Notice, Order or Document Rules, 2004
 - The Procedure for Conducting Inquiry Against a Member of Appropriate Commission Rules, 2004
 - The Procedure for Holding Inquiry by Adjudicating Officer Rules, 2004
 - The Appellate Tribunal for Electricity Salary, Allowances and Other Conditions of Service of the Officers and Employees Rules, 2004 *as amended by (Amendment) Rules, 2011*
 - The Intimation of Accidents (Form and Time of Service of Notice) Rules, 2005
 - The Forum of Regulators Rules, 2005
 - The National Load Despatch Centre Rules, 2005
 - The Distribution of Electricity Licence (Additional Requirements of Capital Adequacy, Creditworthiness and Code of Conduct) Rules, 2005
- and much more...(see detailed Contents inside)*

2013

**BARE ACT
WITH SHORT NOTES**

Price ₹ 130

Universal
Law Publishing Co. Pvt. Ltd.
NEW DELHI - INDIA

Web : www.jainbookagency.com
E-mail : sales@jainbookagency.com

JAIN BOOK AGENCY

C-9, Opp. 'B' Block, Metro Station, Connaught Place,
New Delhi-110001, Tel. +91 11 44556677 & 23416390 to 94
Fax +91 11 41513850

(2) In the absence of express provision to the contrary in this Act, or any rule made thereunder, an appeal from the decision of a Chief Electrical Inspector or an Electrical Inspector shall lie to the Appropriate Government or, if the Appropriate Government, in special order so directs, to an Appropriate Commission.

163. Power for licensee to enter premises and to remove fittings or other apparatus of licensee.—(1) A licensee or any person duly authorised by a licence may, at any reasonable time, and without the consent of the occupier of his intention, enter any premises to which electricity is, or has been, supplied by him, of any premises or land, under, over, along, across, in or upon which the electric supply-lines or other works have been lawfully placed by him for the purpose of—

- (a) inspecting, testing, repairing or altering the electric supply-lines, meters, fittings, works and apparatus for the supply of electricity belonging to the licensee; or
- (b) ascertaining the amount of electricity supplied or the electrical quantity contained in the supply; or
- (c) removing where a supply of electricity is no longer required, or where the licensee is authorised to take away and cut off such supply, any electric supply-lines, meters, fittings, works or apparatus belonging to the licensee.

(2) A licensee or any person authorised as aforesaid may also, in pursuance of a special order in this behalf made by an Executive Magistrate and after giving not less than twenty-four hours notice in writing to the occupier,—

- (a) enter any premises or land referred to in sub-section (1) for any of the purposes mentioned therein;
- (b) enter any premises to which electricity is to be supplied by him, for the purpose of examining and testing the electric wires fittings, works and apparatus for the use of electricity belonging to the consumer.

(3) Where a consumer refuses to allow a licensee or any person authorised as aforesaid to enter his premises or land in pursuance of the provisions of sub-section (1) or sub-section (2), when such licensee or person has so entered, refuses to allow him to perform any act which he is authorised by those sub-sections to perform, or fails to give reasonable facilities for such entry or performance, the licensee may, after the expiry of twenty-four hours from the service of a notice in writing on the consumer, cut off the supply to the consumer for so long as such refusal or failure continues, but for no longer.

164. Exercise of powers of Telegraph Authority in certain cases.—The Appropriate Government may, by order in writing, for the placing of electric lines or electrical plant for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communications necessary for the proper co-ordination of works, confer upon any public officer, licensee or any other person engaged in the business of supplying electricity under this Act, subject to such conditions and restrictions, if any, as the Appropriate Government may think fit to impose and to the provisions of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), any of the powers which the telegraph authority possesses under that Act with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained.

165. Amendment.—The provisions of sub-section (1) clause (a) of section 162 of the Act, 1894 (1 of 1894) shall be amended as follows:—

(2) The Appropriate Commission shall, in any special order so directs, to an Appropriate Commission, a person, not being a member of the Commission, direct that he may, at any reasonable time, and without the consent of the occupier of his intention, enter any premises to which electricity is, or has been, supplied by him, of any premises or land, under, over, along, across, in or upon which the electric supply-lines or other works have been lawfully placed by him for the purpose of—

166. Coordination forum.—The Appropriate Government may, by order in writing, constitute a coordination forum consisting of the Chief Electrical Inspector, Members thereof, representatives of the electric supply companies and the electric supply industry in the country.

(2) The Centre for Co-ordination shall consist of the Chief Electrical Inspector, State Commissioner for Electricity and the Chairperson of the Forum of regulated electricity supply companies in the country.

(3) The Chairperson of the Forum shall be a person who has been engaged in the business of electricity supply for smooth and continuous supply of electricity.

(4) The State Commission shall be the Chairperson of the Forum of regulated electricity supply companies in the country.

(5) There shall be a sub-committee of the Appropriate Government consisting of the Chief Electrical Inspector, State Commissioner for Electricity and the Chairperson of the Forum of regulated electricity supply companies in the country.

(a) to co-ordinate the distribution of electricity in the country.

(b) to regulate the supply of electricity in the country.

(c) to provide for the smooth and continuous supply of electricity in the country.

167. Exemption from provisions of certain cases.—The provisions of section 163 shall not apply to any licensee, such electricity supply company, or person engaged in the business of supplying electricity under this Act, who is insolvent or under liquidation.

168. Protection of persons engaged in the business of supplying electricity.—No proceeding shall be instituted against any Member, Chief Electrical Inspector, State Commissioner for Electricity, or any other person engaged in the business of supplying electricity, for any offence committed by him in the discharge of his duties as such officer, unless a complaint has been filed by an assessing officer or a person authorised by the Appropriate Government in this behalf, and the Appropriate Government has sanctioned the proceedings thereunder.

169. Membership of Commission to be appointed by Government.—The Appropriate Government may, by order in writing, constitute a Commission consisting of the Chief Electrical Inspector, State Commissioner for Electricity and the Chairperson of the Forum of regulated electricity supply companies in the country.

The Indian Telegraph Act, 1885

(13 of 1885)

with

- The Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933)
- The Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950 (74 of 1950)
- The Outdoor Use of Wireless Equipment (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2007
- The Use of very low power Radio Frequency devices or equipments including the Radio Frequency Identification Devices (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2009
- The Use of very low power Radio Frequency devices, for indoor applications in the 13.553-13.567 MHz Frequency range (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2010
- The Use of low power devices or Equipments for Indoor applications in the 433 to 434 MHz Frequency range (Exemption from licensing Requirement) Rules, 2012

2013

**BARE ACT
WITH SHORT NOTES**

Price ₹ 50

Universal
 Law Publishing Co. Pvt. Ltd.
 NEW DELHI - INDIA

Web : www.jainbookagency.com
 E-mail : sales@jainbookagency.com

JAIN BOOK AGENCY

C-9, Opp. 'B' Block, Metro Station, Connaught Place,
 New Delhi-110001, Tel. +91 11 44556677 & 23416390 to 94
 Fax +91 11 41513850

9B. Crediting of sum to Consolidated Fund of India.—Money received towards the Universal Service Obligation under section 9 shall first be credited to the Consolidated Fund of India, and the Central Government may, if Parliament by appropriation made by law in this behalf so provides, credit such proceeds to the Fund from time to time for being utilised exclusively for meeting the Universal Service Obligation.

9C. Grants and loans by the Central Government.—The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, credit by way of grants and loans such sums of money as that Government may consider necessary in the Fund.

9D. Administration and utilisation of Fund.—(1) The Central Government shall have the power to administer the Fund in such manner as may be prescribed by rules made under this Act.

(2) The Fund shall be utilised exclusively for meeting the Universal Service Obligation.

(3) The Central Government shall be responsible for the co-ordination and ensuring timely utilisation and release of sums in accordance with the criteria as may be prescribed by rules made under this Act.]

PART III

POWER TO PLACE TELEGRAPH LINES AND POSTS

10. Power for telegraph authority to place and maintain telegraph lines and posts.—The telegraph authority may, from time to time, place and maintain a telegraph line under, over, along, or across, and posts in or upon, any immovable property:

Provided that—

(a) the telegraph authority shall not exercise the powers conferred by this section except for the purposes of a telegraph established or maintained by the ¹[Central Government], or to be so established or maintained;

(b) the ¹[Central Government] shall not acquire any right other than that of user only in the property under, over, along, across, in or upon which the telegraph authority places any telegraph line or post; and

(c) except as hereinafter provided, the telegraph authority shall not exercise those powers in respect of any property vested in or under the control or management of any local authority, without the permission of that authority; and

(d) in the exercise of the powers conferred by this section, the telegraph authority shall do as little damage as possible, and, when it has exercised those powers in respect of any property other than that referred to in clause (c), shall pay full compensation to all persons interested for any damage sustained by them by reason of the exercise of those powers.

1. Subs. by the A.O. 1937, for "Government".

11. Pow
or posts.—
repairing,
under, ove

Pro

12. Pow
subject to
10, clause
thinks fit to
necessarily
section, or
connected
under those

13. Pow
or post.—
has been pl
any proper
and the loc
the telegrap
removed or
telegraph a

14. Pow
authority n
Act in respo
local author
supply of g

Provide

(a)

(b)

15. Dis
dispute ari
consequenc
clause (c), o
telegraph at
or otherwis
be determin
generally on

1. Subs. by

REGIONAL HEAD QUARTER

Total Exec. - 73

Reg. Head
 E1-E5 -2, SUP-1, SUP -20
 ASST-1, STENO - W/M -34
 TOTAL-127

Vigilance
 E1-E5 -2, SUP-1, STENO-1

Reg. Ping & Perf. Rev. Cell to ED
 E6 -1
 E1-E5 -2
 STENO-1
 ATTDI-1

ES-EPA-1 DRIVER-1
 ATTDI-1

Law

DGM/AGM
 System PIng**

F & A
 DGM
 E6 -2
 E1-E5 -12

O&M

Const
 PAPS-1
 ACCOUNTANT-2
 ASSISTANT-0
 STENO -2
 ATTDI

Project
 AGM/ GM
 E6/E7 -4
 E1-E5 -15
 PAPS -1-3
 SUP -2
 STENO-2
 ATTDI -1

Oprn. & Maint.
 AGM/ GM
 E6/E7-3
 E1/E5-11
 PAPS-1-7
 STENO-3
 ATTDI-1

HR
 DGM
 E1-E6 -9
 PAPS -1-5
 SUP -5
 STENO-2
 ASST -5
 ATTDI-2

Comm.
 DGM
 E1-E6 -4
 PAPS 1
 SUP -5
 STENO-1
 ATTDI-1

Chief Mgr./ DGM

Chief Mgr./ DGM

Site Incharge

Station Incharge

** will not be operative at present

For Plain 1 Ex for 200 KM
 1 Supr. for 150 KM
 1 W/M for 75 KM
 For Hilly 1 Ex for 100 KM
 1 Supr. for 50 KM
 1 W/M for 25 KM

Station in-charge E6/E7 - 1

STENO-2; ATTENDET - 1; DRIVER-1

Materials Stores

E1-E5 - 1
 STOREKEEPER - 1
 WM-1

HR Admn. & Civil Maint.

E1-E5 - 1
 SUPR - 2

Finance

E1-E5 - 1
 SUPR - 1

S/S O&M

S/S Maint.

E1-E5 - 3
 SUPR - 2
 WM- 4
 *Maintenance planning.
 *Maintenance logs.
 *Routine Inspection & Maintenance
 *Major maint.
 *Fault detection & repair

S/S Opern.

*Liaison with CPCC/RSCC
 *Switching
 *Trippings reports
 *Sys.tem monitoring & records

E6- 1

E1-E5 - 4; SUPR - 4
 WM - 4

T. L Maint.

*Stores records

*Inventory control

*Post award contracts management

*Procurement

*Leave records

*Payroll admn.

*Payroll administration
 *Staff welfare of local procurement & payments

*Maintenance of s/s bldg. & housing colony

*Payroll administration

*Administration of local procurement & payments

*Maintenance of s/s bldg. & housing colony

*Maintenance logs.

*Routine Inspection & Maintenance

*Major maint.
 *Fault detection & repair

*Trippings reports

*Sys.tem monitoring & records

*Safety records
 *Incident reporting
 *First aid & safety training

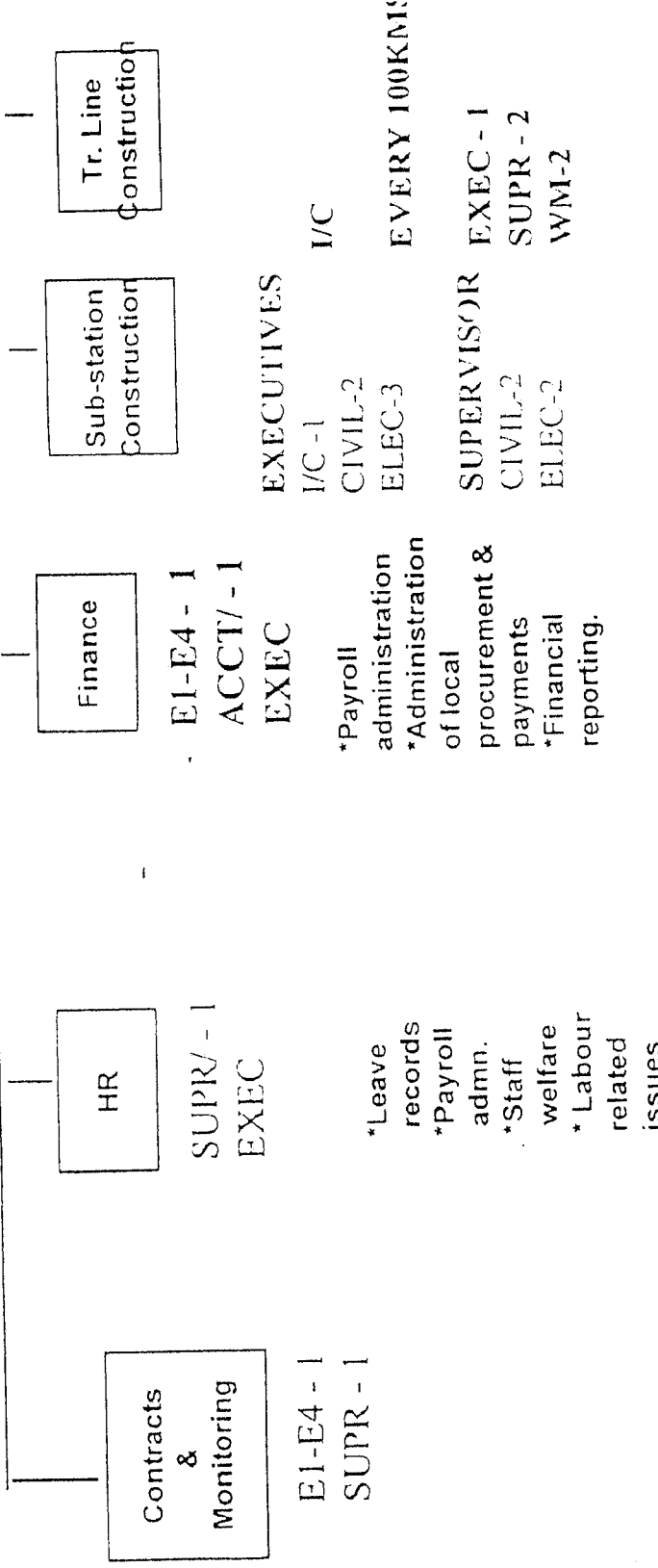
*Maintenance logs

*Routine Inspection & Maintenance

*Major maint.
 *Fault detection & repair

Handwritten signature

****Construction Chief**
E6/E7 - 1
STENO-2;ATTENDET-1



****Except for HVDC stations**

Handwritten signature

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD.
(Corporate HRD Division)

CIRCULAR

Ref: C:HRD:ED:

Dated: 12-09-97

Employees Dev. Scheme - Technicians & Secretarial Personnel

Various issues relating to Technician training programme & Secretarial training programme have been under consideration for quite sometime. In this regard, there have been references also from various regional offices. The issues have been dealt upon in detail and the following guidelines shall be applicable for Technician training programme and Secretarial training programme, with immediate effect:-

1.0 TECHNICIAN TRAINING

1.1 Eligibility criteria.

- 1.1.1 Workmen in W3 grade and above are eligible subject to the following:-
- 1.1.2 Maximum age limit of 40 years.
- 1.1.3 VIII pass or successful completion of basic education course in POWERGRID..
- 1.1.4 Passing the prescribed screening test, if any.
- 1.1.5 W2 employees, actually working in technical areas are also eligible. In exceptional cases, W2 employees from non-technical areas may also be considered, provided the employees are surplus in that area and no replacement would be necessary under any condition.

1.2 Duration & Nature of training.

- 1.2.1 Training will be of 6 months duration.
- 1.2.2 Centralised test will be conducted by Corporate HRD on completion of training. Those who qualify the test will be redesignated as Technician in the same grade.

1.3 Seniority / Promotion

- 1.3.1 Seniority in the grade will be reckoned from the date of entry into the grade. However, promotion on the basis of acquiring Technician training can be allowed only with prospective effect, on the next standard date of promotion.

To illustrate: A is an Attendant in W4 grade since 1.1.90. He was redesignated as Technician based on the Technician training in June 1998. In this case, seniority of A will count from 1.1.90. However, he will be considered for promotion only w.e.f. 1.7.98 i.e. after completing the Technician training, on the immediate next standard date i.e. 1st July.

dhx

10/12

1.4 Equivalence of training for purpose of career.

1.4.1 Successful completion of 6 months Technician training will be deemed to be equivalent to ITI qualification in POWERGRID.

1.5 Past cases

1.5.1 Technician training programmes of 3 months duration, conducted earlier will not be considered equivalent to ITI. Employees, who had undergone the 3 months training will be provided further 3 months training and if they successfully complete the same and pass the centralised test at the end of training, to be conducted by Corporate HRD, will be deemed to possess qualification equivalent to ITI.

1.5.2 Employees who have already been redesignated in Technician cadre based on 3 months training will continue to be designated as Technicians and will have avenues to move to higher grade as per promotion policy and the channels of promotion, wherever ITI is not a requisite qualification.

1.5.3 In case of employee redesignated as Technician in W1/W2 level, minimum eligible period of five years for consideration for promotion will continue to apply.

2.0 SECRETARIAL TRAINING

2.1 Eligibility criteria for undergoing training

2.1.1. Workmen in W4 & above grade are eligible subject to the following:-

2.1.2 Maximum age limit of 45 years.

2.1.3 Matric pass & above.

2.1.4 Passing the prescribed screening test, if any.

2.1.5 Only such employees in W4 & above grade would be considered who are surplus in the existing place and can be spared without any substitute.

2.2 Duration & Nature of training.

2.2.1 Training will be of six months duration.

On completion of training, stenography examination @ 80 w.p.m. & 40 w.p.m. will be conducted as per COP in vogue. Those who qualify will be redesignated in the same grade of Secretarial cadre.

2.3 Seniority / Promotion

2.3.1 Seniority in the grade will count from the date of entry into the grade. However, promotion on the basis of acquiring Secretarial training can be allowed only with prospective effect, on the next standard date of promotion.

Law

2.4 Past Cases

2.4.1 Those employees in W3 level, who have successfully completed secretarial training, can be redesignated as Jr. Asstt. (Steno-Typist). Further promotion to them to W4 will be subject to passing typing and shorthand test @ 40/80 w.p.m. respectively, apart from other considerations as per COP.

3.0 GENERAL

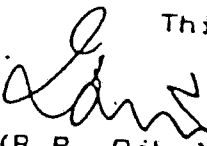
3.1 Procedure for nomination

3.1.1 Number of slots for training in a batch for each region will be notified by Corporate HRD in consultation with Corporate HRM. The number of slots identified would be on the basis of vacancy / requirement and related considerations.

3.1.2 Based on the nominations received, screening will be done for selecting the employee to undergo training programme.

3.1.3 The training programmes will be followed by final exam centrally administered by Corporate HRD, in association with Corporate HRM.

This issues with the approval of competent authority.


(R.P. Ojha)
DGM (HRD)

Distribution :

A. CORPORATE CENTRE

ED - C&M/ENGG/FIN/LD&C/VIG
GM - OS&SO/CMG/MATLS/ENGG/BDD/QA&I/HRD
AGM- CP/CS/CONSTN.MGT.&ENVT./F&A/GRIEV.CELL/COMML
DGM- ENGG-TL,S/STN.&C&I/COST ENGG/CS/F&A/HRM/SKC,AJ/CO.
SECY. /IPP/LAW/JV
CM - HRM (IRK,BDK/KND/RPS), EDP
MGR- FIN (ESTT.)

B. REGIONS

ED - WR & SR
GM (I/C) - ER & NER/NR
GM - SRTS/SRLDC
AGM (I/C) - NR-I/NR-II/ER/NER/WR/WRLDC
DGM (I/C) - NRLDC/ERLDC/NERLDC
Heads of Regional : FINANCE/C&M/O&M

CC : FOR KIND INFORMATION TO :

CMD
DIR. (PERS.)
DIR. (PROJ.)